



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 233]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 17, 2013/आश्विन 25, 1935

No. 233]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 17, 2013/ASVINA 25, 1935

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 2013

जांच की शुरुआत

विषय : चीन जन. गण. के मूल के या वहां से निर्यातित केबल टाईज के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा (एस एस आर) पाटनरोधी जांच ।

सं. 15/20/2013—डीजीएडी.—वर्ष 1995 में और उसके बाद यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे “नियमावली” कहा गया है), को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे प्राधिकारी कहा गया है), ने चीन जन.गण. और चीनी ताइपेई (जिसे आगे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के या वहां से निर्यातित केबल टाईज (जिसे आगे संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी ।

2. यतः प्राधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2008 की अधिसूचना सं० 14/10/2007—डीजीएडी के तहत संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों के बारे में मूल जांच शुरु की थी । चीन जन.गण. और चीनी ताइपेई (जिसे आगे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के या वहां से निर्यातित केबल टाईज (जिसे आगे संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करते हुए प्राधिकारी ने 23 सितंबर, 2008 को प्रारंभिक जांच परिणाम जारी किए थे । अनंतिम शुल्क 31 अक्तूबर, 2008 की सी.शु. अधिसूचना सं. 118/2008 के तहत लागू किया गया था । प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित केबल टाईज के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करते हुए 31 मार्च, 2009 को अपने अंतिम जांच परिणाम जारी किए थे । संबद्ध वस्तु पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क 30 अप्रैल, 2009 की सी.शु. अधिसूचना सं. 44/2009—सी.शु. के तहत लगाया गया था ।

3. और यतः समीक्षा जांच के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकारी को घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करते हुए मै. स्पोर लॉक प्लास्टिक्स प्रा. लि., मुंबई से एक आवेदन प्राप्त हुआ जिसमें संबद्ध देशों के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा की पुष्टि की गई और जिसमें संबद्ध वस्तु पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क को बढ़ाने/उसमें संशोधन करने का अनुरोध किया गया था ।

4. यतः प्राधिकारी ने 4 अक्टूबर, 2011 की अधिसूचना सं. 15/10/2011—डीजीएडी के तहत चीन जन.गण. और चीनी ताइपेई के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों के संबंध में मध्यावधि समीक्षा (एमटीआर) जांच शुरू की थी और प्राधिकारी ने 3 अक्टूबर, 2012 की अधिसूचना सं. 15/10/2011—डीजीएडी के तहत संबद्ध देशों के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर संशोधित पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी । प्राधिकारी की सिफारिशों के आधार पर केन्द्र सरकार ने 14 दिसंबर, 2012 की अधिसूचना सं. 56/2012 के तहत दोनों संबद्ध देशों से हुए आयातों पर संशोधित पाटनरोधी शुल्क लागू किया गया था ।

5. यतः मै0 स्पोरलॉक प्लास्टिक्स प्रा. लि. ने भारत में संबद्ध वस्तु के घरेलू उद्योग के रूप में चीनी ताइपेई के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन और परिणामी क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना का आरोप लगाते हुए उक्त अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार प्राधिकारी के समक्ष अब एक विधिवत पुष्टीकृत आवेदन दायर किया है और संबद्ध देशों के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने, उसे जारी रखने और उसमें वृद्धि करने का अनुरोध किया है ।

घरेलू उद्योग

6. निर्णायक समीक्षा हेतु यह आवेदन भारत में संबद्ध वस्तु के घरेलू उद्योग के रूप में मै. स्पोरलॉक प्लास्टिक्स प्रा. लि., मुंबई ने दायर किया है । उपलब्ध सूचना के अनुसार आवेदक का उत्पादन संबद्ध वस्तु के भारतीय उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है और इसलिए वह नियमों के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग है ।

विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

7. मूल जांचों, मध्यावधि समीक्षा और वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद “केबल टाईज” है । वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा होने के कारण विचाराधीन उत्पाद वही रहता है जैसा कि मूल जांच और मध्यावधि समीक्षा जांच में था । वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद केबल टाईज है । केबल टाईज में एकीकृत गियर रैक के साथ कठोर नाइलॉन टेप होता है । एक छोर पर छोटे खुले खांचे के भीतर एक रैचेट होता है । यह केबल/वायर बंधिंग प्रणालियों की मित्त्वययी तथा लोचशील पद्धति है । केबल टाईज को कई नामों अर्थात् नॉन-रिलीजेबल या रिलीजेबल (पुनः प्रयोज्य) टैगों, स्ट्रैपों, जिप टाईज, टाई रैप, रैट बैल्ट आदि से जाना जाता है और इनका उत्पादन तथा बिक्री ग्राहकों की जरूरत के अनुसार अलग-अलग आकारों में की जाती है । केबल टाईज एकल नग में ढाली गई युक्ति होती है जिसमें बांधने और स्वतः तालाबंद होने की युक्ति वाला धातु का कोई कांटा या भारी भरकम पच्चर नहीं होता है । नॉन-रिलीजेबल केबलटाई को एक बार खींचने के बाद इसे वापस नहीं लाया जा सकता, केबल जोर से खींचा जा सकता है । केबल टाईज सामान्यतः एकल प्रयोग की मुक्तियां होती हैं । तथापि, ग्राहकों की मांग के अनुसार पुनः प्रयोज्य केबल टाईज का उत्पादन भी किया जाता है ।”

यह उत्पाद सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 39 के उपशीर्ष 3926.9010 के अंतर्गत वर्गीकृत है । तथापि, सीमा-शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और जांच के क्षेत्र पर किसी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है ।

8. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु भौतिक एवं तकनीकी विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देशन कीमत, वितरण एवं विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण जैसे मापदंडों के संबंध में आयातित उत्पाद के समान वस्तु है ।

निर्णायक समीक्षा की शुरुआत

9. दायर किए गए विधिवत पुष्टीकृत आवेदन को ध्यान में रखते हुए पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार प्राधिकारी संबद्ध देशों के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में लागू पाटनरोधी शुल्क को निरंतर लागू रखने की जरूरत की समीक्षा करने और इस बात की जांच करने कि क्या ऐसे शुल्क की समाप्ति से पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, के लिए निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करते हैं ।

शामिल देश

10. इस जांच में शामिल देश चीन जन.गण. और चीनी ताइपेई हैं ।

जांच अवधि

11. वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच अवधि 1 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2013 (12 माह) तक की है । तथापि, क्षति विश्लेषण में अप्रैल, 2009—मार्च, 2010, अप्रैल 2010—मार्च, 2011, अप्रैल, 2011—मार्च, 2012 की अवधि तथा जांच अवधि शामिल होंगे ।

प्रक्रिया

12. वर्तमान निर्णायक समीक्षा में दिनांक 31 मार्च, 2009 की अधिसूचना सं. 14/10/2007—डीजीएडी के तहत प्रकाशित मूल जांच के अंतिम जांच परिणाम और 3 अक्टूबर, 2012 की अधिसूचना सं. 15/10/2011 के तहत प्रकाशित मध्यावधि समीक्षा जांच परिणाम के सभी पहलू शामिल हैं ।

13. उपर्युक्त नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के उपबंध इस समीक्षा में आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे ।

सूचना प्रस्तुत करना

14. संबद्ध देशों में ज्ञात निर्यातकों, भारत में उनके दूतावासों के जरिए उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले भारत में आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने और निम्नलिखित पते पर प्राधिकारी को अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है :

निर्दिष्ट प्राधिकारी

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,

वाणिज्य विभाग,

कमरा सं. 240, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011

15. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से जांच से संगत अपने अनुरोध कर सकता है ।

समय-सीमा

16. वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई हेतु कोई अनुरोध इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस (40) दिनों से पूर्व उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में पहुंच जाना चाहिए । यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी है तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमों के अनुसार, “उपलब्ध तथ्यों” के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं ।

17. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस इस जांच की शुरुआत की तारीख से 40 दिनों के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा पाटनरोधी उपाय जारी रखने की जरूरत अथवा अन्यथा के बारे में घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें ।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

18. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के बारे में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो उसे दो अलग-अलग सैटों (क) गोपनीय रूप में अंकित (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) और (ख) अगोपनीय रूप में अंकित दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) में प्रस्तुत किया जाना चाहिए । प्रस्तुत की गई समस्त सूचना पर प्रत्येक पृष्ठ के सबसे ऊपर स्पष्ट रूप से “गोपनीय” या “अगोपनीय” अंकित होना चाहिए ।

19. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे । समस्त हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय रूपांतरण की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय रूपांतरण की पांच (5) प्रतियां प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

20. गोपनीय रूप में दावा की गई सूचना हेतु, सूचना प्रदाता के लिए यह अपेक्षित है कि वह प्रदान की गई सूचना के साथ इस आशय के यथोचित कारण का एक विवरण उपलब्ध कराए कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता और/अथवा ऐसी सूचना का सारांश क्यों संभव नहीं है ।

21. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई/सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है । अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके । तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है; तो प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है ।

22. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं । प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं ।

23. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी रिकॉर्ड में नहीं ले सकते हैं । संतुष्ट होने और प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत को स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे ।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

24. नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं ।

असहयोग

25. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं ।

जे. एस. दीपक, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th October, 2013

INITIATION**Subject : Sunset Review (SSR) Anti-dumping Investigation concerning imports of Cable Ties, originating in or exported from China PR and Chinese Taipei**

F. No.15/20/2013-DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and thereafter (hereinafter referred as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred as the Rules), the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) recommended imposition of Anti-dumping Duty on imports of "Cable Ties" (hereinafter referred as the subject goods), originating in or exported from China PR and Chinese Taipei (hereinafter referred to as the subject countries).

2. Whereas, the original investigation concerning imports of the subject goods from the subject countries was initiated by the Authority vide notification No. 14/10/2007-DGAD dated 1st January, 2008. The preliminary finding was issued by the Authority on 23rd September, 2008, recommending provisional Anti-dumping Duty on the imports of Cable Ties (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from China PR and Chinese Taipei (hereinafter referred to as subject countries). The provisional duties were imposed vide Customs Notification No 118/2008 dated 31st October, 2008. The Authority notified its final findings on 31st March 2009 recommending definitive Anti-dumping Duty on the imports of Cable Ties originating in or exported from subject countries. The definitive Anti-dumping Duty was imposed on the subject goods vide Customs Notification No. 44/2009 -Customs, dated 30th April, 2009.

3. And whereas in terms of the provisions for review investigations, the Authority received an application from M/s. Surelock Plastics Pvt. Ltd. Mumbai representing domestic industry which substantiated the need for midterm review of the Anti-dumping Duty imposed on the subject goods originating in or exported from the subject countries and requested for enhancement/revision of the Anti-dumping Duty imposed on subject goods.

4. Whereas, the Authority initiated a mid-term review (MTR) investigation in respect of the imports of the subject goods, originating in or exported from China PR and

Chinese Taipei, vide notification No. 15/10/2011-DGAD dated 4th October, 2011 and the Authority vide Notification No. 15/10/2011-DGAD dated 3rd October, 2012 recommended modified Anti-dumping Duty imposed on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries. On the basis of the recommendations of the Authority, the Central Government vide Notification No. 56/2012 dated 14th December, 2012 imposed modified anti dumping duty on imports from both the subject countries.

5. Whereas, M/s. Surelock Plastics Pvt. Limited have now filed a duly substantiated application before the Authority, as a domestic industry of the subject goods in India, in accordance with the Act and the Rules, alleging likelihood of continuation or recurrence of dumping of the subject goods, originating in or exported from China PR and Chinese Taipei and consequent injury to the domestic industry and have requested for review, continuation and enhancement of the anti-dumping duties imposed on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries.

Domestic Industry

6. The application for the sunset review has been filed by M/s. Surelock Plastics Pvt. Limited, Mumbai as domestic industry of the subject goods in India. As per the information available, the applicant accounts for a major proportion in Indian production of the subject goods and therefore constitute the domestic industry within the meaning of the Rules.

Product under consideration and Like Article

7. The product under consideration, in the original investigations, mid-term review as well as the present sunset review investigation, is “Cable Ties”. The present investigation being a sunset review, the product under consideration remains the same as in the original and mid-term review investigation. The product under consideration in the present petition is Cable Ties. Cable Ties consists of sturdy nylon tape with an integrated gear rack and on one end a ratchet within a small open case. This is an economical and versatile method of Cable/Wire bunching systems. Cable Ties are known by several names e.g. non-releasable or releasable (reusable) tags, straps, zip ties, tie wrap, rat belt etc. and produced & sold in different sizes as per requirement of the customers. Cable Ties are a one piece moulded mechanism with no metal barbs or cumbersome wedges having fastening and self locking device. Once a non-releasable cable tie is pulled through, it prevents from being pulled back allowing tighter pulling only. Cable ties are generally single use devices. However reusable Cable Ties are also produced according to the demand of the customers.”

The product is classified under Chapter 39 of Customs Tariff Act under subheading 3926.9010. The Customs classification is, however, indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation

8. The petitioner has claimed that the goods produced by the domestic industry are like article to the imported product in terms of parameters such as physical & technical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification.

Initiation of Sunset Review

9 In view of the duly substantiated application filed and in accordance with Section 9A(5) of the Act, read with Rule 23 of the Anti-dumping Rules, the Authority initiates a sunset review investigation to review the need for continued imposition of anti dumping duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the

subject countries and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

Countries involved

10 The countries involved in this investigation are China PR and Chinese Taipei.

Period of Investigation

11 The Period of Investigation (POI) for the purpose of the present review is from 1st April, 2012 to 31st March, 2013 (12 months). However, injury analysis shall cover the periods April, 2009-March, 2010, April, 2010-March, 2011, April, 2011-March, 2012 and the POI.

Procedure

12 The present sunset review covers all aspects of the final findings of the original investigation published vide Notification No. 14/10/2007-DGAD dated 31st March, 2009 and the mid-term review investigation findings published vide Notification No. 15/10/2011 dated 3rd October, 2012.

13 The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rules supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

Submission of Information

14 The known exporters in the subject countries, the Government of the subject countries through its embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

The Designated Authority
Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties
Ministry of Commerce and Industry
Department of Commerce
Room No. 240, Udyog Bhavan, New Delhi-110011.

15 Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

Time Limit

16 Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-dumping Rules.

17 All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to continue or otherwise the Anti-dumping measures within 40 days from the date of initiation of this investigation.

Submission of information on confidential basis

18 In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non-Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either “confidential” or “non-confidential” at the top of each page.

19 Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and five (05) copies of the non-confidential version must be submitted by all the interested parties.

20 For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

21 The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out/ summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

22 The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

23 Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of public file:

24 In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

25 In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

J. S. DEEPAK, Designated Authority